conditions of tariff were under negotiation between AES and the Government of Orissa. Subsequently, cost estimates of the project were scrutinised by Orissa State Electricity Board (OSEB) and followed by techno-economic clearance by Central Electricity Authority (CEA) in the month of August, 1994. Further, at the time of the finalisation of PPA, Government of Orissa and OSEB had detailed negotiations with AES before signing the final Power Purchase Agreement (PPA) in the month of January, 1995 for this project.

विज्ञापन प्रसारण के लिए शुल्क लगाए जाने संबंधी मानदंड

2058. **श्री अजीत जोगी:**
श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन को चालू वर्ष में अब तक विज्ञापनों के प्रसारण से कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है;

(ख) विज्ञापनों के प्रसारण हेतु शुल्क प्रभावित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) किस विज्ञापन कंपनी से तथा किन-किन विज्ञापनों से अधिकतम राजस्व की प्राप्ति हुई है;

(घ) क्या अधिक विज्ञापनों के कारण आधे घंटे की अवधि के धारावाहिकों का प्रसारण मात्र बीस मिनट में हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव): (क) 1.4.95 से 31.7.95 की अवधि के दौरान अर्जित सकल राजस्व 107.50 लाख रुपए है।

(ख) विज्ञापन दर सूची ढांचा कार्यक्रम के प्रसारण समय, कार्यक्रम की लोकप्रियता तथा नेटवर्क की पहुंच जैसे कारकों के संयोजन द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(ग) निम्नलिखित एजेंसियों ने डीडी-1 तथा डीडी-2 के कार्यक्रमों पर अत्यधिक व्यवसाय किया:—

(1) क्रिएटिव आई, (2) फेम कम्युनिकेशन्स, (3) निम्बस कम्युनिकेशन्स, (4) सागर एन्टरप्राइजेज़, (5) मीडिया एशिया, तथा (6) लिंटास इण्डिया, आदि। उत्पादवार रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(घ) से (च) जी, नहीं तथापि, दूरदर्शन विज्ञापनों से अधिक व्यवसायिक राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से कई प्रकार के कार्यक्रमों जिनके दर्शकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, में अधिक संख्या में विज्ञापन बुक करता है।

Loan ceiling enhanced by IDBI

2059. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state.

(a) whether it is a fact that recently Small Industries Development Bank of India has enhanced the ceiling on soft loan assistance under National Equity Fund (NEF) scheme from 15% to 25% to SSI units; if so, what are the details thereof;

(b) the eligibility of the entrepreneurs to avail such assistance; and

(c) whether SIDBI will directly provide this assistance referred to in part 'a' above or under refinance scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) Yes, Sir. The Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has enhanced the ceiling on soft loan assistance from the present level of 15% of the project cost subject to a maximum of Rs. 1.5 lakh per project to 25% of the project cost subject to a maximum of Rs. 2.5 lakh per project. There is however no change in the existing level of promoter's contribution at 10% of the project cost. The following projects/entrepreneurs are eligible to avail such assitance.

(i) New projects in tiny and small scale sectors for manufacture, preservation or processing of goods irrespective of the location (except for the units in metropolitan areas)

(ii) Existing tiny and small scale industrial units and service enterprises undertaking expansion, modernisation, technology upgradation and diversification irrespective of location (except in metropolitan areas)

(iii) Sick units in the tiny and small scale sectors including service enterprises which are considered potentially viable.

(c) SIDBI has reported that the entire soft loan assistance under the scheme is provided through the State Financial Corporations/twin function State Industrial Development Corporations eligible public and private sector bank and urban co-operative bank who are acting as agents of SIDBI.

ग्रामीण बैंकों द्वारा उठाये गये घाटे

2060. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई, 1995 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण बैंकों को कुल कितना घाटा हुआ;

(ख) देश में इन ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं और कौन-कौन सी शाखाएं लाभ में चल रही हैं और

(ग) क्या उनका बड़े बैंकों के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) संचयी घाटों के संबंध में जानकारी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार रखी जाती है। दिनांक 31 मार्च, 1994 की स्थिति (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संचयी घाटे 1302.53 करोड़ रुपए (अनन्तिम) के थे।

(ख) नाबार्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 1995 को देश में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14549 शाखाएं (अनन्तिम) थीं। लाभ उठा रही शाखाओं की संख्या के बारे में जानकारी नाबार्ड में उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Modernisation of Powerlooms in Maharashtra

2061. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Maharashtra Government has sent any proposal to the Centre for financial assistance for modernisation of powerlooms in that State; and

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government therein indicating the present stage of consideration of the proposal?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Increase in Government expenditure due to wage revision in PSUs

2062. SHRI GAYA SINGH: will the Minister FINANCE be pleased to state:

(a) what is the increase in the Government expenditure due to wage revision on 1st January, 1992 of Executives Cadre working in the Public Sector; and

(b) what are the details of earning of the Government through Collection of Income Taxes on this increased arrears, give details?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.